(i) Gorakhpui
(2) Kuraaon r -gion
(3) Lch
(4) Silchar
(5) AUeppey/1 richur
(6) Towang
(7) Longding Niausa)
(8) Koloriang
(9) Anini

Projects for the remaining stations are under preparation.

CRITICISM AOAINSI NEWSPRINT POLICY

364. SHRI M. SRINIVASA REDDY :
SHRI \ ADINARAYANA REDI Y :

Will the Minist, • of INFORMATION AND BROADCASTING AND COM-MUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Newsprint policy of th< Government of India has been severely c i ticised by the Indian and Eastern New paper Society ; and

(b) if so. whethi r Government propose to make suitable modifications in the newsprint policj

THE MINIST |R OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADC VSTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (S tfRI I. K- GUJRAL) : (a) and (b) The L dian and Eastern Newspaper Society hav I made representations to Government against its Newsprint Allocation Policy i or 1969-70. A formal reply to the Socie *f* will be sent shortly –

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में वन-भूमि

365. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री पीताम्बर दास :
श्री मान सिंह वर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कितने प्रतिशत भूमि को वन-भूमि माना गया है और वार्षिक वन्य उपज का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस उपज का क्या उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि वहां सरकार द्वारा लगाई गई एक विशाल आरा-मशीन घाटे में चल रही है; यदि हां तो हानि की राशि कितनी है और उसके क्या कारण हैं और घाटे को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या वहां कागज के कारखाने जैसे वन्य उपज से संबंधित उद्योग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

•(•[FOREST AREA IN ANDAMAN AND NICOBAR: ISLANDS

365. SHRf J' [P]- YADAV :
SHRI PITAMBER DAS :
SHRI MAN SINGH VARMA

Will the Minister of FOOD AND' AGRICULTURE be pleased to state :

fa) the percentage of the area of land in Andaman and Nicobar islands which has been treated as forest area; and the details of annual forest produce ;

(b) the use to which this produce is put to by Government ;

(c) whether it is a fact that the huge-saw-mill installed there by Government is running at a loss, if so, what is the amount of the loss incurred, and what are the reasons therefor and what steps are being taken to obviate the loss ;

(d) whether any industries, like paper mills connected with forest produce are proposed to be set up there ; and

* (c) if so, the details thereof ?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह की 73 प्रतिशत भूमि को वन क्षेत्र समझा जाता है। वनों का वार्षिक उत्पाद प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न होता है । फिर भी 1967-68 का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) इमारती लकड़ी 71052 घन मीटर

(2) बल्लीज	.	397740 की संख्या में
(3) बांस	.	954949 की संख्या में
(4) इंधन की लकड़ी		13657 कॉर्ड्स
(5) बेंत	.	4026400 की संख्या में
(6) धूप लीसा	.	3187 किलोग्राम

(ख) वन उत्पाद का निम्न प्रकार से निपटान किया जाता है :—

(1) इमारती लकड़ी के कुन्दों का :—

(क) द्वीप और मुख्य भूमि पर स्थानीय प्लाइवुड कारखानों और माचिस कारखानों को विक्रय।

(ख) मुख्य भूमि पर संभरण और निपटान महा-निदेशालय के द्वारा रेलवे विभाग और कलकत्ते और मद्रास के विभागीय डिपुओं द्वारा दूसरे सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थानों को विक्रय।

(ग) चैथम और वैतापुर की विभागीय आरा मिलों में इनका रूपान्तर कर स्थानीय जनता और सरकारी विभागों के साथ साथ मुख्य भूमि पर कलकत्ता और मद्रास के विभागीय डिपुओं को निपटान के लिये विक्रय।

(घ) गैर सरकारी आरा मिलों को अपनी मिलों में इनके रूपान्तरण के लिये विक्रय।

(2) बोलीज और बांसों का प्रयोग सरकारी विभागों व जनता, दोनों के ही द्वारा अस्थायी हटमेन्ट्स और बाड़ आदि के लिये प्रयोग किया जाता है।

(3) इंधन की लकड़ी मुख्यतः वाष्प प्रचालित जहाजों और बिजली घरों को चलाने में प्रयुक्त की जाती है।

(4) वन विभाग द्वारा बेंत का प्रयोग लकड़ी के कुन्दों का "बेडा" बनाने में किया जाता है और इसका एक अंश जोत और कुटीर उद्योग विभाग द्वारा फर्नीचर बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

(6) पट्टेदारों द्वारा एकत्र किया जाने वाला धूप लीसा उनके द्वारा सीधा ही बेच दिया जाता है।

(ग) जी हां, सरकार द्वारा चैथम में स्थापित आरामिल हानि पर चल रही है। वन विभाग के गत तीन वर्षों के कच्चे लेखे के आंकड़ों के आधार पर, प्रति वर्ष औसत हानि 35,96,228 रुपये निकलती है। हानि के मुख्यतः कारण ये हैं :—(1) विभाग द्वारा अपनायी गयी वाणिज्यिक प्रणाली के आधार पर लकड़ी के कुन्दों का अधिक मूल्य; (2) निम्न कोटि के लकड़ी के कुन्दों को चीरने से चीरी हुई इमारती लकड़ी की बहुत ही कम प्राप्ति होती है; (3) पुरानी और पुराने माडल की मशीनों और उपकरणों का प्रयोग; (4) आरे के मिल में प्रयोग किये जाने वाले सामान की लागत में वृद्धि; (5) सेवा की उदार शर्तों के कारण औद्योगिक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि; और (6) द्वीप समूह और मुख्य भूमि पर चीरी हुई लकड़ी का उत्पादन लागत से कम मूल्य पर विक्रय।

हानि के निवारण के लिये उठाये गये कदम निम्न हैं :—(1) कच्चे लेखे में कच्ची सामग्री की लागत का पुनः परीक्षण; (2) निर्धारित कार्य क्रम के रूप से पुरानी और पुराने माडल वाले यंत्रों और उपकरणों को बदलना; और (3) स्थानीय बिक्री के लिये चीरी हुई लकड़ी की दरों में वृद्धि करने पर विचार।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE) :

(a) Seventy-three per cent. of land are of Andaman and Nicobar Islands has been

†[ ] English translation.

treated as forest area. The annual forest produce varies from year to year. The details for 1967-68 are howeveer as follow :

(i) Timber—71052 cubic metre.
(ii) Ballies—397740 numbers.
(iii) Bamboos—954949 numbers.
(iv) Firewood—13657 cords.
(v) Canes—4026400 numbers.
(vi) Dhup resin—3187 kilograms.

(b) The forest produce is disposed of mainly in the following ways :—

(i) Timber logs by—

(a) sale to local Plywood Factories and to the Match factories on the Island and the mainland;

(b) on the mainland by sale to the Railways through Directorate General of Supplies and Disposals and other Government and Semi-Government Institutions through the Departmental Depots at Calcutta and Madras ;

(c) conversion in departmental Saw Mills at Chatham and Betapur for local sale to the local public and Government Deptts. as well as for disposal in the Departmental Depots in the mainland at Calcutta and Madras ;

(d) sale to private Saw Millers for conversion in their Saw Mills.

(ii) Ballies and Bamboos are used both by Government Departments as well as Public in making temporary hutments fencing etc.

(iii) Firewood is used mainly for running of Steam-Vessels and Power House ;

(iv) Canes are used by Forest Departments for rafting of logs and part of it is utilised by Jail and Cottage Industries Department for furniture making.

(vi) Dhoop Resin extracted by lesses is disposed of by them directly.

(c) Yes, Madam. The saw-mill installed at Chatham by Government is running at a loss. Based on the figures given in the proforma accounts of the forest Department for the last three years the average annual loss works out to Rs. 35,96,228. Reasons for losses mainly are—(i) High Cost of logs as fixed by the commercial system of accounting adopted by the Department ; (ii) sawing of inferior quality logs yields poor out-turn of sawn-timber ; (iii) Use of old and out-moded machinery and equipment ; (iv) increase in the cost of stores used in the saw mill ; (v) increase in pay and allowances given to the industrial employees due to liberalised service conditions ; and (vi) sale of sawn timber in the Islands and on the mainland markets at rates lower than the cost of production.

Steps taken to obviate the losses are (1) re-examination of costing of raw-materials in proforma accounts (2) replacement of old and out-moded machinery and equipment on phased basis ; and (3) consideration for increase in the rates for local sale of sawn timber.

(d) No, Madam.

(e) Does not arise.]

बरियारपुर स्थित उप-डाक-तार-घर के कर्मचारियों के लिए सुख सुविधाएं

366. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरियारपुर के उप-डाक-तार घर के लिये दो डाक चपरासियों की सिफारिश होने पर भी वहां केवल एक ही डाक चपरासी है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां कर्मचारियों के लिये रहने की जगह, टेलीफोन सेवा आदि जैसी आवश्यक सुख-सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां तो सरकार इन त्रुटियों को कब तक दूर करने का विचार रखती है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?